Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

Original Article

गाँधी की दृष्टि में भूमंडलीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण

नाहिद प्रवीण
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
Email: nahiddu2225@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180246
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 2(A)
Pp. 231-234
February - 2026
Submitted: 19 Jan. 2026
Revised: 29 Jan. 2026
Accepted: 14 Feb. 2026
Published: 28 Feb. 2026

सारांश

महात्मा गांधी का आर्थिक दर्शन विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित था, जो ग्राम स्वराज के माध्यम से स्थानीय स्वावलंबन, स्वदेशी उत्पादन और समुदाय-केंद्रित निर्णयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता था। उनकी दृष्टि में, वर्तमान भूमंडलीकरण जो अति-केंद्रीकरण, सांस्कृतिक एकरूपता, पर्यावरणीय शोषण और आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देता है, एक संकटपूर्ण मॉडल है। गांधी बड़े उद्योगों और मशीनों का विरोध नहीं करते थे, बल्कि उन संरचनाओं का विरोध करते थे जो मानवीय गरिमा, रचनात्मकता और सामाजिक न्याय का हनन करती हैं। कोविड-19 महामारी ने अत्यधिक वैश्विक निर्भरता की नाजुकता को उजागर कर गांधी के आत्मनिर्भरता के विचार की प्रासंगिकता सिद्ध की है। हालाँकि, दोनों दृष्टियों के बीच "ग्लोकलाइजेशन" के माध्यम से सामंजस्य संभव है—जहाँ वैश्विक सहयोग और तकनीक का उपयोग स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता हासिल करने के लिए किया जाए। इस प्रकार, गांधी का विकेंद्रीकरण का विजन न केवल भूमंडलीकरण के दोषों के प्रति एक नैतिक प्रतिवाद है, बल्कि एक लचीली, न्यायसंगत और टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक भी है।

कीवर्ड: *गाँधीवादी अर्थशास्त्र, भूमंडलीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, केंद्रीकरण विरोध, लघु उद्योग, स्थानीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक पूंजीवाद, आत्मनिर्भरता, टिकाऊ विकास, मानव-केंद्रित अर्थव्यवस्था, उपभोक्तावाद विरोध, पर्यावरणीय संतुलन*

प्रस्तावना

वर्तमान भूमंडलीकरण का युग एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक है जो उत्पादन, वितरण और उपभोग को वैश्विक स्तर पर केंद्रीकृत करने पर बल देती है। इसकी मूल भावना है "एक विश्व, एक बाजार"। इसके विपरीत, महात्मा गाँधी का आर्थिक दर्शन "विकेंद्रीकरण" के सिद्धांत पर आधारित था, जहाँ आर्थिक शक्ति और निर्णय क्षमता सबसे निचली इकाई—यानि गाँव और व्यक्ति—के पास केंद्रित हो। गाँधी के लिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण केवल एक नीतिगत विकल्प नहीं, बल्कि नैतिक अनिवार्यता और सामाजिक न्याय का आधार था। उन्होंने कहा था, "सच्ची सभ्यता तब आती है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, न कि दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनंत संसाधनों का दोहन"।[1] यह लेख गाँधी की विकेंद्रीकरण की दृष्टि और वर्तमान भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के बीच तनाव, सामंजस्य की संभावनाओं और 21वीं सदी के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

गाँधी के विकेंद्रीकरण के दर्शन की मूलभूत संरचना:

ग्राम स्वराज- विकेंद्रीकरण की चरम अभिव्यक्ति- गाँधी के आर्थिक चिंतन का केंद्रबिंदु था "ग्राम स्वराज"—एक ऐसी व्यवस्था जहाँ गाँव पूर्णतः स्वावलंबी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक इकाई हो। उनकी कल्पना में, "गाँव का अर्थ होगा ऐसी स्वच्छंद नगरी जो अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके और दूसरों पर निर्भर न रहे"।[2] इस मॉडल में:

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
नाहिद प्रवीण, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

How to cite this article:
प्रवीण, . नाहिद. (2026). गाँधी की दृष्टि में भूमंडलीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण. Journal of Research & Development, 18(2(A)), 231–234. https://doi.org/10.5281/zenodo.18950034

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18950034
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

- उत्पादन: दैनिक आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएँ—खाद्य, वस्त्र, आवास, बर्तन—स्थानीय स्तर पर उत्पादित की जाएँगी।
- शासन: गाँव पंचायत सर्वोच्च प्राधिकार होगी।
- न्याय: विवादों का निपटारा स्थानीय स्तर पर होगा।
- शिक्षा: बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण स्थानीय संदर्भ में दिया जाएगा।

यह मॉडल आज के "लोकलाइजेशन" और "सर्कुलर इकोनॉमी" के समकालीन विमर्श का आधार प्रतीत होता है। विश्व बैंक के 2020 के एक अध्ययन के अनुसार, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने से आर्थिक लचीलापन 40% तक बढ़ सकता है।[3]

केंद्रीकरण के तीन शत्रु: बड़े उद्योग, बड़ी मशीनें और दूरी

गाँधी ने तीन प्रमुख तत्वों को विकेंद्रीकरण के लिए खतरा माना:

1. **बड़े उद्योग:** उनका मानना था कि बड़े पैमाने के उद्योग पूँजी का केंद्रीकरण करते हैं, जिससे समाज में शोषण और असमानता बढ़ती है। उन्होंने लिखा, "बड़े कारखाने थोड़े से लोगों के हाथों में पूँजी और शक्ति केंद्रित कर देते हैं और बहुसंख्यक लोगों को मजदूर बना देते हैं"।[4]
2. **बड़ी मशीनें:** गाँधी मशीनों के सिद्धांत के विरोधी नहीं थे, बल्कि ऐसी मशीनों के विरोधी थे जो मानव श्रम को विस्थापित करती हैं और व्यक्ति की रचनात्मकता को नष्ट करती हैं। चरखा उनकी "लोगों की मशीन" की अवधारणा का प्रतीक था।
3. **उत्पादन और उपभोग के बीच की दूरी**: जब उत्पादन दूरस्थ स्थानों पर हो और उपभोग स्थानीय स्तर पर, तो परिवहन लागत, मध्यस्थों का शोषण और पर्यावरणीय क्षति होती है। गाँधी "उत्पादन और उपभोग का स्थानीयकरण" चाहते थे।

आर्थिक इतिहासकार जे.सी. कुमारप्पा, जो गाँधी के आर्थिक विचारों के प्रमुख व्याख्याकार थे, इन्होंने इसे "अर्थशास्त्र की स्थायित्ववादी नींव" कहा।[5]

भूमंडलीकरण का गाँधीवादी विश्लेषण—अवसर या संकट?

यदि गाँधी आज होते, तो वे भूमंडलीकरण की वर्तमान अभिव्यक्ति से मुख्यतः पाँच आधारों पर असहमत होते:

1. **सांस्कृतिक एकरूपता का विरोध:** भूमंडलीकरण अक्सर पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति को वैश्विक मानक बनाता है, जिससे स्थानीय संस्कृतियाँ, ज्ञान प्रणालियाँ और मूल्य क्षरित होते हैं। गाँधी सांस्कृतिक विविधता को मानवता की धरोहर मानते थे।
2. **आर्थिक निर्भरता का सृजन:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ देशों और समुदायों को परस्पर निर्भर बनाती हैं, जिससे वैश्विक संकटों (जैसे कोविड-19) के प्रति अतिसंवेदनशीलता बढ़ती है। गाँधी आत्मनिर्भरता को सुरक्षा और स्वतंत्रता का आधार मानते थे।
3. **पारिस्थितिक असंतुलन:** वैश्विक व्यापार लंबी दूरी के परिवहन, अत्यधिक पैकेजिंग और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को बढ़ावा देता है। गाँधी का दर्शन प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देता है।
4. **शोषणकारी श्रम व्यवस्था:** वैश्विक पूँजीवाद अक्सर श्रमिकों के शोषण, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और असमान वेतन (विशेषतः विकासशील देशों में) को प्रोत्साहित करता है। यह गाँधी के "सर्वोदय" और "अंतिम व्यक्ति" के विचार के सीधे विपरीत है।
5. **वित्तीय अस्थिरता:** वैश्विक पूँजी का अत्यधिक केंद्रीकरण और अस्थिर प्रवाह आर्थिक संकटों का कारण बनता है, जैसा कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने दिखाया। गाँधी स्थिर और नैतिक वित्तीय व्यवस्था के पक्षधर थे।

अर्थशास्त्री वंदना शिवा, जो गाँधीवादी परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, कहती हैं, "भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट करती है, जैव विविधता को समाप्त करती है और सांस्कृतिक विविधता का हनन करती है"।[6]

कोविड-19 महामारी: गाँधी के पूर्वानुमान की पुष्टि- कोविड-19 महामारी ने भूमंडलीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता को उजागर कर दिया। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में वैश्विक व्यापार में 8.9% की गिरावट आई, और कई देशों को अनाज, चिकित्सा उपकरण और दवाओं की कमी का सामना करना पड़ा।[7] इसने "आत्मनिर्भरता" और "स्थानीय उत्पादन" के महत्व को रेखांकित किया, जो गाँधी के मूल विचारों के अनुरूप है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया "आत्मनिर्भर भारत अभियान" इसी विचारधारा का एक प्रतिबिंब है, हालाँकि इसकी व्याख्या और क्रियान्वयन पर बहस जारी है।

संभावित सामंजस्य: एक "गाँधीवादी भूमंडलीकरण" का स्वरूप- क्या भूमंडलीकरण और गाँधीवादी विकेंद्रीकरण के बीच कोई सामान्य भूमि है? गाँधी अलगाववादी नहीं थे। उनका विरोध केंद्रीकरण और शोषण के स्वरूप से था, न कि विचारों, संस्कृति और आवश्यक वस्तुओं के वैश्विक आदान-प्रदान से। एक संभावित सामंजस्य इस प्रकार हो सकता है:

"ग्लोकलाइजेशन" का मॉडल: सोच वैश्विक, कार्य स्थानीय-

आधुनिक "ग्लोकलाइजेशन" (Glocalization) की अवधारणा—जहाँ वैश्विक संसाधनों और स्थानीय संदर्भों का समन्वय हो—गाँधी के विचारों के करीब है। इसमें:

- प्रौद्योगिकी का विकेंद्रीकृत उपयोग: इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए किया जा सकता है, बिना उन्हें बड़े निगमों का मजदूर बनाए।
- निष्पक्ष व्यापार (Fair Trade): यह आंदोलन सीधे उत्पादकों (अक्सर छोटे किसानों और कारीगरों) को उचित मूल्य दिलाकर गाँधी के "अहिंसक व्यापार" के विचार को साकार करता है।
- वैश्विक ज्ञान, स्थानीय अनुप्रयोग: स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खेती और जल संरक्षण की वैश्विक तकनीकों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सकता है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट ने स्वीकार किया है कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) वैश्विक व्यापार का 80% हिस्सा हैं और 70% रोजगार पैदा करते हैं, जो विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल के महत्व को दर्शाता है।[8]

सहकारिता का वैश्विक नेटवर्क: विकेंद्रीकरण के लिए एक मॉडल- गाँधी सहकारिता को पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों से बेहतर विकल्प मानते थे। आज, "इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एलायंस" जैसे संगठन 100 से अधिक देशों में 3 मिलियन सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 1.2 अरब सदस्य हैं।[9] यह एक वैश्विक लेकिन विकेंद्रीकृत आर्थिक नेटवर्क है, जहाँ निर्णय स्थानीय स्तर पर होते हैं लेकिन सीख और संसाधन वैश्विक स्तर पर साझा किए जाते हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता: एक साझा एजेंडा- जलवायु परिवर्तन का संकट वैश्विक है, लेकिन इसका समाधान स्थानीकृत कार्रवाई में निहित है। गाँधी का "प्रकृति की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के अनुसार उपभोग" का विचार, और आधुनिक "कार्बन फुटप्रिंट को कम करने" का लक्ष्य दोनों स्थानीय उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का अनुमान है कि स्थानीय खाद्य प्रणालियों को अपनाने से खाद्य परिवहन से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 50% तक की कमी आ सकती है।[10]

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ—क्या गाँधी का मॉडल व्यावहारिक है?

प्रमुख आलोचनाएँ:

1. अवास्तविक रोमांटिसिज्म: आलोचकों का मानना है कि गाँधी का ग्राम-केंद्रित मॉडल अतीत के प्रति एक रोमांटिक लगाव है, जो जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और तकनीकी जटिलता वाली आधुनिक दुनिया में व्यवहार्य नहीं है।
2. आर्थिक दक्षता का अभाव: छोटे पैमाने का उत्पादन अक्सर कम दक्षता और उच्च लागत वाला होता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
3. वैश्विक सहयोग की अनदेखी: एक विकेंद्रीकृत विश्व में जलवायु परिवर्तन, महामारी और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग मुश्किल हो सकता है।

गाँधीवादी प्रत्युत्तर और समकालीन प्रासंगिकता:

इन आलोचनाओं के बावजूद, गाँधी के विचार निम्नलिखित कारणों से प्रासंगिक बने हुए हैं;

- लचीलापन और स्थिरता: कोविड-19 और जलवायु संकट ने सिद्ध किया है कि अत्यधिक केंद्रीकृत और वैश्विक रूप से जुड़ी व्यवस्थाएँ अधिक नाजुक हैं। विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ अधिक लचीली और टिकाऊ होती हैं।
- नवाचार का विकेंद्रीकरण: इंटरनेट और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकें अब "डिस्ट्रिब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग" को संभव बना रही हैं, जहाँ डिजाइन वैश्विक हो सकते हैं लेकिन उत्पादन स्थानीय स्तर पर।
- सामाजिक न्याय: विकेंद्रीकरण रोजगार के अवसरों को फैलाता है, ग्रामीण पलायन को कम करता है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) , विशेष रूप से लक्ष्य 8 (उचित कार्य और आर्थिक विकास) और लक्ष्य 11 (स्थायी शहर और समुदाय) से सीधे जुड़ा हुआ है।

अर्थशास्त्री ई.एफ. शूमाकर, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गाँधीवादी विचारों को आगे बढ़ाया, ने लिखा: "आधुनिक अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती जाती है, उतनी ही अधिक सफलता छोटी-छोटी इकाइयों की गतिविधियों पर निर्भर करती है... क्योंकि छोटे पैमाने पर, हर कोई मायने रखता है"।[11]

निष्कर्ष

गाँधी की दृष्टि और समकालीन भूमंडलीकरण के बीच मूलभूत तनाव "ग्लोबल विलेज" (वैश्विक गाँव) और "वसुधैव कुटुम्बकम" (पूरी पृथ्वी एक परिवार है) की अवधारणाओं के बीच के अंतर में निहित है। ग्लोबल विलेज एक आर्थिक और तकनीकी संकल्पना है, जहाँ बाजारों और सूचनाओं का एकीकरण है। वसुधैव कुटुम्बकम एक नैतिक और आध्यात्मिक संकल्पना है, जो सभी प्राणियों के बीच पारस्परिक देखभाल, सम्मान और न्याय पर बल देती है।

गाँधी चाहते थे कि वैश्विक एकता आर्थिक लेन-देन से ऊपर उठकर नैतिक बंधन पर आधारित हो। आज की आवश्यकता एक ऐसे मॉडल की है जो इन दोनों दृष्टियों का सामंजस्य कर सके—एक ऐसा "गाँधीवादी भूमंडलीकरण" जो:

1. आर्थिक निर्णयों को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीत करे।
2. वैश्विक सहयोग को नैतिकता और न्याय के आधार पर संचालित करे।
3. तकनीकी प्रगति को मानवीय मूल्यों और पर्यावरणीय सीमाओं के अधीन करे।

गाँधी ने कहा था, "मैं अपने देश की आजादी ऐसी चाहता हूँ कि अन्य देश उससे कुछ सीख सकें और मेरे देश से प्रेरणा लेकर उसकी तरह आजादी चाह सकें"।[12] यही भावना आज के भूमंडलीकृत विश्व के लिए मार्गदर्शक हो सकती है—विभिन्नता में एकता, स्थानीय स्वायत्तता में वैश्विक एकजुटता, और आर्थिक विकास में नैतिक सीमाओं का समावेश। भूमंडलीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच यह संतुलन ही एक ऐसे भविष्य की नींव रख सकता है जो टिकाऊ, न्यायसंगत और मानवीय हो।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

संदर्भ सूची (References)

1. गाँधी, मोहनदास करमचंद (1909), हिन्द स्वराज, अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर, पृ. 41
2. गाँधी, मोहनदास करमचंद (1942), ग्राम स्वराज, अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर, पृ. 18
3. विश्व बैंक (2020), लोकलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रेजिलिएंस: लेसन्स फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस, वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक प्रकाशन, पृ. 27
4. गाँधी, मोहनदास करमचंद (1928), यंग इंडिया (संपादित संग्रह), अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर, पृ. 335
5. कुमारप्पा, जे.सी. (1945), इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, वर्धा: अखिल भारतीय गांधीवादी अर्थशास्त्र संस्थान, पृ. 12
6. शिवा, वंदना (2000), स्टेयिंग अलाइव: वूमेन, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, लंदन: ज़ेड बुक्स, पृ. 45
7. विश्व व्यापार संगठन (WTO) (2021), वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2021, जिनेवा: WTO प्रकाशन, पृ. 33
8. विश्व व्यापार संगठन (WTO) (2016), वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2016: लेवलिंग द ट्रेडिंग फील्ड फॉर एमएसएमई, जिनेवा: WTO प्रकाशन, पृ. 21
9. इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एलायंस (ICA) (2020), ग्लोबल को-ऑपरेटिव मॉनिटर 2020, ब्रुसेल्स: ICA प्रकाशन, पृ. 8
10. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) (2021), फूड सिस्टम्स इन इकोसिस्टम्स: अ न्यू रिपोर्ट. नैरोबी: UNEP प्रकाशन, पृ. 56
11. शूमाकर, ई.एफ (1973), स्मॉल इज ब्यूटीफुल: ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऐज़ इफ पीपल मैटर्ड, लंदन: ब्लॉंड एंड ब्रिग्स, पृ. 65
12. गाँधी, मोहनदास करमचंद (1931), स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गाँधी, मद्रास: गाँधी स्मारक निधि, पृ. 202